

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वासि मंत्री (श्री सिकन्दर बल्ल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1976 से प्रत्येक श्रेणी में बनाए गए फ्लैटों के 25 प्र० श० फ्लैट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए हैं ।

(ख और ग). निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग की किसी भी योजना की श्रणियों के अधीन आबंटित प्लॉटों में से 15 प्र० श० प्लॉट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाते हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्लॉटों के आबंटियों की ओर से मकान बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Ratio of Irrigated Area in M.P.

2537. SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether ratio of the total irrigated area of the State of M.P. is much less than the national ratio; and

(b) if so, what are the steps contemplated by the Central Government to remove the disparity?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, formulated, investigated and implemented by the State Governments. However, the Government of India have given a high priority to development of irrigation in the developmental programmes of the State.

The following measures are being taken in this connection:—

(i) Higher outlays for early completion of the major/medium on-going schemes;

(ii) Taking up of new schemes under the major/medium irrigation sector;

(iii) Maximum priority in the allocation of funds within the State Governments resources, mobilising institutional investment from banks with the support of the ARDS and the World Bank to the maximum extent possible, maximum emphasis on rural electrification programme for providing electric power to irrigation pumps for minor irrigation works; and

(iv) Systematic renovation and modernisation of ex-Malguzari which are in derelict condition due to siltation so as to regain the lost irrigation potential.

बिहार की 'काम के लिए भोजन' कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं

2538. श्री रीत लाल प्रसाद बर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'काम के लिए भोजन' कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार की कितनी परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, और

(ख) उनमें से कितनी मंजूर हुई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख). बिहार सरकार ने 'काम के लिए भोजन' योजना के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कों के निर्माण तथा लघु सिंचाई